"मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।" इस कथन की वर्तमान भारतीय मीडिया के 'कॉर्पोरेट स्वामित्व' (Cross-media ownership) के संदर्भ में समीक्षा कीजिए।

"मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है" यह उक्ति इस विश्वास पर टिकी है कि प्रेस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की निगरानी करेगा और जनता को जागरूक रखेगा। हालाँकि, वर्तमान भारतीय संदर्भ में 'कॉर्पोरेट स्वामित्व' (Corporate Ownership) और 'क्रॉस-मीडिया स्वामित्व' (Cross-media ownership) ने इस स्तंभ की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

नीचे इस कथन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा दी गई है:

1. क्रॉस-मीडिया स्वामित्व: एक गहराता संकट

जब एक ही कॉर्पोरेट समूह प्रिंट (अखबार), इलेक्ट्रॉनिक (टीवी), रेडियो और डिजिटल मीडिया जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर नियंत्रण रखता है, तो उसे क्रॉस-मीडिया स्वामित्व कहा जाता है।

* सूचना का संकुचन: यदि गिने-चुने कॉर्पोरेट घराने ही अधिकांश मीडिया आउटलेट्स के मालिक होंगे, तो जनता तक पहुँचने वाले विचारों की विविधता (Plurality of views) समाप्त हो जाती है।

* एकाधिकार (Monopoly): रिलायंस (Network18), अडानी (NDTV) और टाइम्स ग्रुप जैसे बड़े समूहों का दबदबा यह तय करता है कि देश में "नैरेटिव" क्या होगा।

2. कॉर्पोरेट स्वामित्व के नकारात्मक प्रभाव

मीडिया अब एक 'मिशन' के बजाय 'बिज़नेस मॉडल' बन गया है, जिसके निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं:

* हितों का टकराव (Conflict of Interest): जब मीडिया मालिक के अन्य व्यावसायिक हित (जैसे खनन, ऊर्जा या बुनियादी ढांचा) होते हैं, तो मीडिया संस्थान उन क्षेत्रों में सरकार की कमियों को उजागर करने से बचते हैं ताकि उनके मुख्य व्यवसाय को नुकसान न हो।

* संपादकीय स्वतंत्रता का ह्रास: कॉर्पोरेट बोर्ड का दबाव संपादकों की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। खबरों का चयन जनहित के बजाय 'कॉर्पोरेट एजेंडे' या 'लाभ' के आधार पर होने लगता है।

* पेड न्यूज़ और सनसनीखेज (TRP की दौड़): मुनाफे की भूख ने गंभीर पत्रकारिता को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे 'पेड न्यूज़' और 'मीडिया ट्रायल' जैसी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं।

3. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट

कॉर्पोरेट नियंत्रण ने मीडिया की 'वॉचडॉग' (Watchdog) भूमिका को 'लैपडॉग' (Lapdog) में बदलने का जोखिम पैदा कर दिया है:

> "जब मीडिया संस्थान खुद एक बड़े कॉर्पोरेट साम्राज्य का हिस्सा होते हैं, तो वे सत्ता से कठिन सवाल पूछने के बजाय सत्ता के साथ 'क्रोनी कैपिटलिज्म' (Crony Capitalism) का हिस्सा बन जाते हैं।"

4. नियामक ढाँचे का अभाव

भारत में अभी भी क्रॉस-मीडिया स्वामित्व को रोकने के लिए कोई सख्त कानून या व्यापक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ने कई बार इस पर चिंता जताई और सिफारिशें दीं, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

निष्कर्ष

यद्यपि तकनीक और डिजिटल मीडिया ने सूचना का लोकतांत्रीकरण किया है, लेकिन बड़े पूंजीपतियों द्वारा मीडिया के स्वामित्व ने इसकी साख पर बट्टा लगाया है। यदि मीडिया को वास्तव में लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' बने रहना है, तो स्वामित्व में पारदर्शिता, संपादकीय स्वायत्तता की सुरक्षा और क्रॉस-मीडिया होल्डिंग्स पर उचित विनियामक सीमाएं तय करना अनिवार्य है।